पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राजेश कुमार गुप्ता एवं अन्य

बनाम

सपना कुमारी एवं अन्य

2018 की दीवानी विविध क्षेत्राधिकार संख्या 1235

11 सितम्बर, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या विवादित विधवा के रूप में सपना कुमारी को मृतक वादी की विधिक प्रतिनिधि मानकर आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. के अंतर्गत सहवादी के रूप में प्रतिवेश करने का आदेश, बिना आदेश 22 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत जांच किए, वैधानिक रूप से टिकाऊ है?

हेडनोट्स

एक बार जब याचिकाकर्ता ने मृतक जवाला प्रसाद गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी/वैधानिक प्रतिनिधि के रूप में सपना कुमारी के प्रतिस्थापन पर आपत्ति जताई, तो अधीनस्थ न्यायालय को सी.पी.सी. की आदेश 22, नियम 5 के अंतर्गत एक जांच करानी चाहिए थी और उस जांच के परिणाम के अनुसार ही कार्य करना चाहिए था। बिना किसी जांच के सपना कुमारी को मृतक जवाला प्रसाद गुप्ता की कानूनी उत्तराधिकारी/वैधानिक प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता था। (पैरा 20)

अर्ज़ी स्वीकार की जाती है। (पैरा 21)

न्याय दृष्टान्त

जलादी सगुना (मृतक) बनाम सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट एवं अन्य, (2008) 8 एस.सी.सी. 521; अनिल कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, 2015 एस.सी.सी. ऑनलाइन पट 4903; दशरथ राव काटे बनाम बृज मोहन श्रीवास्तव, (2010) 1 एस.सी.सी. 277; शिव धर्मानंद उर्फ देव शंकर तिवारी एवं अन्य बनाम श्यामलाल चौहान एवं अन्य, 2009 एस.सी.सी. ऑनलाइन पट 1152

अधिनियमों की सूची

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908; परिसीमा अधिनियम, 1963

मुख्य शब्दों की सूची

प्रतिस्थापन; विधिक प्रतिनिधि; आदेश 22 नियम 3 दी.प्र.स.; आदेश 22 नियम 5 सी.पी.सी.; विधवा; जांच; पुनर्विचार; प्रक्रिया संबंधी त्रुटि

प्रकरण से उत्पन्न

स्वत्व वाद संख्या 77/2005 में दिनांक 05.02.2018 को पारित आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री अभिषेक, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं की ओर से: श्री दिवाकर प्रसाद सिंह

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की दीवानी विविध क्षेत्राधिकार संख्या 1235

==

1. राजेश कुमार गुप्ता
2. मुकेश रोशन कुमार
3. राकेश रोशन सभी के पिता- स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद गुप्ता, निवासी- खुस्कीबाग, पोस्ट खुस्कीबाग, थाना सदर पूर्णिया, जिला-पूर्णिया।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सपना कुमारी स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद गुप्ता की कथित विधवा है, निवासी वार्ड नंबर 17, खुस्कीबाग स्टेशन रोड जिसे आम तौर पर नागेश्वरबाग के नाम से जाना जाता है, थाना सदर, जिला पूर्णिया
2. रहफत जहां पति- स्वर्गीय बुलंद अख्तर
3. निशांत जामियाल पिता- स्वर्गीय बुलंद अख्तर
4. इकबाल अख्तर पिता- स्वर्गीय बुलंद अख्तर
5. जमाल अख्तर पिता- स्वर्गीय बुलंद अख्तर
6. सबाना कौसर पिता- स्वर्गीय बुलंद अख्तर
7. कमल अख्तर पिता- स्वर्गीय बुलंद अख्तर
8. फरहाद जहां पिता- स्वर्गीय बुलंद अख्तर
9. निहाल अख्तर पिता- स्वर्गीय बुलंद अख्तर उत्तरदाता 2 से 9 निवासी खुस्कीबाग, थाना सदर,पोस्ट खुस्कीबाग नागेश्वरबाग, जिला पूर्णिया।
10. बेनी चंद्र सरकार पिता सुरेंद्र चंद्र सरकार, निवासी बेलौरी, थाना सदर, पोस्ट बेलौरी, वाया गुलाबबाग, जिला पूर्णिया।

.... उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अभिषेक, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री दिवाकर प्रसाद सिंह

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप कुमार

मौखिक निर्णय

तारीखः11-09-2023

1. यह आवेदन विद्वान उप-न्यायाधीश द्वितीय, *पूर्णिया* द्वारा दिनांक 05.02.2018 को स्वत्व वाद संख्या 77/2005 में पारित आदेश को रद्द करने के लिए है, जिसके तहत निचली अदालत ने याचिकाकर्ता प्रथम द्वारा दायर दी.प्र.स. के आदेश 22, नियम 3 के तहत प्रतिस्थापन याचिका को अनुमति दी है और *सपना कुमारी* को इस मुकदमे में अतिरिक्त रूप से सह-वादी के रूप में प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी गई है।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि यह मामला एकमात्र मृतक वादी *ज्वाला प्रसाद गुप्ता* द्वारा उत्तरदाता द्वितीय समूह और तृतीय समूह के विरुद्ध दायर किए गए शीर्षक वाद संख्या 77/2005 से उत्पन्न हुआ है इसमें राहत के लिए यह दलील दी गई है कि वाद की संपत्ति वादी की घोषित की जाए और उत्तरदाता प्रथम समूह का इससे कोई लेना-देना नहीं है और यह भी घोषित किया जाए कि अतिरिक्त मुंसिफ, पूर्णिया की अदालत द्वारा बेदखली वाद संख्या 24/1996 में पारित डिक्री और उप न्यायाधीश चतुर्थ, पूर्णिया की अदालत द्वारा शीर्षक वाद संख्या 134/1997 में पारित डिक्री गलत, अवैध, कपटपूर्ण, मिलीभगत वाली, शून्य हैं और वादी पर बाध्यकारी नहीं हैं और उन्होंने आगे दलील दी है कि उत्तरदाता द्वितीय समूह किरायेदार हैं और उन्हें वाद वाले घर से बेदखल किया जा सकता है और वादी को वाद वाले घर का कब्जा दिया जा सकता है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि उत्तरदाता प्रथम समूह मुकदमे में उपस्थित हुए और 09.11.2005 को संयुक्त लिखित बयान दायर किया और मुकदमे को लड़ कर रहे हैं और मुकदमे को खारिज करने की प्रार्थना की। उपरोक्त उत्तरदाताओं ने योग्यता पर तकनीकी दलीलों के अलावा मुकदमे की गैर-अनुपालनीयता की दलील सहित विभिन्न दलीलें पेश की। उत्तरदाता प्रथम समूह ने अन्य बचावों के साथ-साथ स्पष्ट रूप से दलील दी कि वाद संपत्ति का निर्माण न तो वादी द्वारा किया गया था और न ही उसके पिता द्वारा, बल्कि उसी संपत्ति के साथ-साथ दो अन्य दुकानों के कमरे, जो एक ही छत के नीचे हैं, का निर्माण उत्तरदाता संख्या 1 के पति और अन्य उत्तरदाताओं के पिता *स्वर्गीय बुलंद अख्तर*

द्वारा किया गया था।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि उत्तरदाता प्रथम समूह ने वादी द्वारा अपने वादपत्र में दिए गए बयान के विरुद्ध एक अतिरिक्त लिखित बयान भी दायर किया है और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा है कि वादी की ओर से यह कहना गलत है कि बेदखली वाद संख्या 24/1996 और स्वामित्व वाद संख्या 134/1997 में पारित आदेश पूरी तरह से गलत, अवैध, धोखाधड़ीपूर्ण, सांठगांठपूर्ण और निराधार हैं और आगे यह भी दलील दी गई है कि वादी किसी भी राहत या राहत पाने का हकदार नहीं है। उन्होंने आगे दलील दी कि मूल एकमात्र वादी *ज्वाला प्रसाद गुप्ता* की मृत्यु 27.02.2015 को हो गई और उनके स्थान पर उनकी पत्नी *सुशीला देवी* से उत्पन्न उनके पुत्रों (यहाँ याचिकाकर्ता) को 25.05.2015 की याचिका के अनुसार वादी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, 19.04.2016 के आदेश द्वारा उत्तरदाता सं. 1 की उपस्थिति में बिना किसी आपत्ति के।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी है कि 20.07.2015 को याचिकाकर्ता *सपना कुमारी* ने दी.प्र.स. के नियम 3 के आदेश 22 के तहत एक याचिका दायर की और अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद मूल वादी *ज्वाला प्रसाद गुप्ता* ने 06.02.2013 को उत्तरदाता प्रथम समूह अर्थात् सपना कुमारी से दोबारा विवाह किया और यह विवाह बिहार विवाह पंजीकरण नियमों के तहत विधिवत पंजीकृत है और प्रार्थना की कि सपना कुमारी को उनके पति स्वर्गीय *ज्वाला प्रसाद गुप्ता*, जो इस मुकदमे के एकमात्र वादी थे, के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में मुकदमे में सह-वादी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए। हालाँकि, बाद में 19.4.2016 के आदेश को वापस लेने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई। 10.05.2016 को उत्तरदाता प्रथम समूह/उत्तरदाता द्वितीय समूह ने दिनांक 20.07.2015 की याचिका पर एक प्रत्युत्तर दायर किया और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि *सपना कुमारी* की प्रतिस्थापन याचिका बहुत विलम्बित है और समय समाप्त होने के कारण इसे अस्वीकार किया जाना उचित है। याचिकाकर्ताओं-प्रतिस्थापित वादियों ने

01.06.2016 को उत्तरदाता दायर कर *सपना कुमारी* उत्तरदाता संख्या 1 की प्रार्थना पर आपत्ति जताई और इस प्रार्थना को अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि 27.06.2016 को उत्तरदाता प्रथम समूह *सपना कुमारी* ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक याचिका दायर की और कहा कि उन्हें वर्तमान मुकदमे की स्थापना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इस कारण वह समय पर प्रतिस्थापन याचिका दायर नहीं कर सकी और उन्होंने 20.07.2015 की उनकी याचिका के मद्देनजर देरी को माफ करने और सह-वादी के रूप में उनके प्रतिस्थापन की अनुमति देने का अनुरोध किया और मूल वादी की कथित विधवा के रूप में उत्तरदाता संख्या 1 का दावा जो 06.02.2013 को मूल वादी के साथ विवाहित होने का दावा करती है उसके अपने आचरण और दस्तावेजों के मद्देनजर पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, उसके द्वारा अपने पहले पति से तलाक से पहले प्राप्त एक आवासीय प्रमाण पत्र भी शामिल है, जो दुर्भावनापूर्ण और अप्रत्यक्ष उद्देश्य से मूल वादी यानी इन याचिकाकर्ताओं के पिता को अपना पति बताता/घोषित करता है और वह पूर्वोक्त धोखाधड़ी से प्राप्त आवासीय प्रमाण पत्र की मदद से *किशनगंज* में एक बहुत पहले का बैंक खाता चला रही है, जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ताओं के पिता को अपना पति बताया गया है। वैवाहिक वाद सं. 48/2016 में पारित दिनांक 20.06.2017 के आदेश की प्रति *सपना कुमारी* द्वारा प्रस्तुत की गई है और इस आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पूर्णिया ने वैवाहिक वाद सं. 48/2016 को अनुरक्षणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है। हालाँकि, विवाह या उसकी वैधता पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि निचली अदालत ने अवैध रूप से और एक विकृत आदेश द्वारा पक्ष आवेदन को प्रतिस्थापन/जोड़ने की अनुमति दी है तथ्यों को समझे बिना और *सपना कुमारी*, कथित कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि की कानूनी

स्थिति से संबंधित प्रश्नों का उचित निर्धारण किए बिना, जो कि दी.प्र.स. के आदेश 22 नियम 5 के तहत अनिवार्य प्रकृति का है।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी है कि आक्षेपित आदेश और उसमें दिए गए कारण *सपना कुमारी* की प्रतिस्थापन याचिका को स्वीकार करने के लिए स्पष्ट रूप से मनमाना है और इसमें पूरी तरह से विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **जलादि सगुण (मृतक) बनाम सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट और अन्य (2008) 8 एससीसी 521** मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है और साथ ही इस न्यायालय के **अनिल कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य हिंदू धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड (2015) एससीसी ऑनलाइन पैट 4903** मामले में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है।

10. उत्तरदातााओं की विद्वान अधिवक्ता *सपना कुमारी* ने यह दलील दी है कि आक्षेपित आदेश सही ढंग से पारित किया गया है और *सपना कुमारी* को सह-वादी के रूप में प्रतिस्थापित करने का निर्देश दिया गया है और उनके प्रतिस्थापन से मुकदमे की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और दी.प्र.स. के आदेश 22, नियम 5 के तहत किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है।

11. उत्तरदातााओं के विद्वान अधिवक्ता ने **दशरथ राव काटे बनाम बृज मोहन श्रीवास्तव (2010) 1 एससीसी** *277* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है और उन्होंने **शिव धर्मा नंद @ देव शंकर तिवारी एवं अन्य बनाम श्याम लाल चौहान एवं अन्य 2009 एससीसी ऑनलाइन पैट** 1152 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है।

12. मैंने पक्षों की दलीलें सुनी है और उन पर विचार किया है।

13. दीवानी प्रक्रिया संहिता का आदेश 22, नियम 5 इस प्रकार हैः-

> ***"जहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति मृत वादी या मृत उत्तरदाताा का कानूनी प्रतिनिधि है या नहीं, ऐसे प्रश्न का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा।"***

14. वर्तमान मामले में, विवाद इस तथ्य को लेकर है कि क्या *सपना कुमारी* मृतक *ज्वाला प्रसाद गुप्ता* की कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि हैं या नहीं। *सपना कुमारी* द्वारा प्रस्तुत मामले से ऐसा प्रतीत होता है कि वह मृतक *ज्वाला प्रसाद गुप्ता* की विधवा होने का दावा करती हैं और उन्होंने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी त्रुटिहीन दस्तावेज नहीं है जो यह साबित कर सके कि वह मृतक *ज्वाला प्रसाद गुप्ता* की विधवा हैं और जैसे ही *सपना कुमारी* के प्रतिस्थापन के संबंध में विवाद उत्पन्न होता है, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई है, आदेश 22, नियम 5 के प्रावधान लागू होते हैं।

15. एक बार जब याचिकाकर्ताओं ने *सपना कुमारी* को प्रतिस्थापित करने पर यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि वह मृतक *ज्वाला प्रसाद गुप्ता* की विधवा नहीं थीं, क्योंकि मृतक *ज्वाला प्रसाद गुप्ता* ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद कभी पुनर्विवाह नहीं किया था, तो न्यायालय का कर्तव्य था कि वह आदेश 22, नियम 5 के तहत इस प्रश्न का निर्णय करे कि क्या *सपना कुमारी* को स्वर्गीय *ज्वाला प्रसाद गुप्ता* की कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सकता है या नहीं।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जलादि सगुण (मृतक) बनाम सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट एवं अन्य (उपरोक्त)** मामले में अनुच्छेद संख्या 9 से 14 तक निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

> *9. जब किसी अपील में उत्तरदाताा की मृत्यु हो जाती है, और मुकदमा करने का अधिकार बच जाता है, तो अदालत द्वारा अपील में आगे बढ़ने से पहले मृतक उत्तरदाताा के कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाना आवश्यक है। जहाँ उत्तरदाताा-वादी, जिसने किसी मुकदमे में सफलता प्राप्त की है, अपील के लंबित रहने के दौरान मर जाता है, उत्तरदाताा द्वारा दायर अपील की सुनवाई के बाद, मृतक उत्तरदाता-वादी के कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाए बिना दिया गया कोई भी निर्णय अमान्य होगा। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, प्रथम उत्तरदाताा (सुगुना) गौण उत्तरदाताा थी और द्वितीय उत्तरदाताा (किरायेदार) केवल एक गौण उत्तरदाता था। जब अपील में प्रथम उत्तरदाताा*

की मृत्यु हो गई, तो उसकी संपत्ति के

14. तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और 19.9.2006 के निर्णय को अपास्त करते हैं, अपील को उच्च न्यायालय की फाइल में पुनः स्थापित करते हैं, निम्नलिखित निर्देशों के साथ:

(i) उच्च न्यायालय पहले मृतका के पति और दूसरी ओर उसकी भतीजियों और भतीजों के बीच विवाद का फैसला करेगा, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य और 28.11.2005 के निष्कर्षों पर विचार करने के बाद और प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की सुनवाई करेगा।

(ii) ऐसे निर्धारण के बाद, मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों को मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख में लाया जाएगा।

(iii) इसके बाद, अपील की योग्यता के आधार पर सुनवाई की जाएगी और कानून के अनुसार उसका निपटारा किया जाएगा।विरुद्ध अपील पर मुकदमा चलाने का अधिकार बच गया। इसलिए अपील को आगे बढ़ाने के लिए मृतक सुगुना के कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाना आवश्यक था।

10. कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए आवेदन दायर करना, कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के बराबर नहीं है। जब एक कानूनी प्रतिनिधि आवेदन दायर किया जाता है, तो अदालत को उस पर विचार करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि क्या उसमें कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में नामित व्यक्तियों को मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिलेख पर लाया जाना चाहिए या नहीं। अदालत द्वारा ऐसा निर्णय होने तक, कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले व्यक्तियों को मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने, न ही मुकदमा चलाने या बचाव करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कानूनी प्रतिनिधि कौन है, इस बारे में कोई विवाद है, तो ऐसे विवाद पर निर्णय दिया जाना चाहिए। केवल तभी जब कानूनी प्रतिनिधि का प्रश्न अदालत द्वारा निर्धारित किया जाता है और ऐसे कानूनी प्रतिनिधि को अभिलेख पर लाया जाता है, यह कहा जा सकता है कि मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व किया गया है। आदेश 22 नियम 5 के तहत कानूनी प्रतिनिधि कौन है, इसका निर्धारण निश्चित रूप से उस मामले के न्यायनिर्णयन के लिए मृतक की संपत्ति के प्रतिनिधित्व के सीमित उद्देश्य के लिए होगा। ऐसे सीमित उद्देश्य के लिए ऐसा निर्धारण, कानूनी प्रतिनिधि माने जाने वाले व्यक्ति को, उस संपत्ति पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा जो मुकदमे का विषय है, मृतक की संपत्ति के अन्य प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के संबंध में।

11. आदेश 22 के नियम 4 और 5 के प्रावधान अनिवार्य हैं। जब

किसी अपील में उत्तरदाताा की मृत्यु हो जाती है, तो न्यायालय केवल यह नहीं कह सकता कि वह मृतक उत्तरदाताा की संपत्ति के सभी प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की सुनवाई करेगा और अपील का निपटारा करेगा। न ही यह उन सभी व्यक्तियों को अपील में पक्षकार बना सकता है जो कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, बिना यह तय किए कि मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, और अपील की सुनवाई योग्यता के आधार पर शुरू कर सकता है। न्यायालय मृतक उत्तरदाताा का कानूनी प्रतिनिधि कौन है, इस बारे में निर्णय को भी अपील के साथ-साथ योग्यता के आधार पर स्थगित नहीं कर सकता। संहिता स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि जहाँ यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति मृतक उत्तरदाता का कानूनी प्रतिनिधि है या नहीं, ऐसे प्रश्न का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। संहिता यह भी प्रावधान करती है कि जहाँ उत्तरदाताााओं में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है और जीवित उत्तरदाताााओं के विरुद्ध मुकदमा करने का अधिकार नहीं रहता, तो न्यायालय, उस ओर से किए गए आवेदन पर, मृतक उत्तरदाताा के कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाएगा और फिर मामले को आगे बढ़ाएगा। हालाँकि नियम 5 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान नहीं है कि कानूनी प्रतिनिधि का निर्धारण अपील की योग्यता के आधार पर सुनवाई से पहले किया जाना चाहिए, नियम 4 और नियम 11 को पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अपील की सुनवाई तभी की जा सकती है जब कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाया जाए।

12. तीसरा उत्तरदाता, जो मृतक का पति है, मृतक के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अभिलेख पर आना चाहता है और ट्रस्ट के इस मामले का समर्थन करना चाहता है कि मृतक द्वारा ट्रस्ट के पक्ष में एक वैध उपहार दिया गया था। दूसरी ओर, अपीलकर्ता वसीयतनामा धारक के रूप में अभिलेख पर आना चाहते हैं, जिनके पक्ष में वाद की संपत्ति वसीयत द्वारा हस्तांतरित की गई थी और मृतक सुगुना की संपत्ति का मध्यस्थ के रूप में प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। वे अपील पर मुकदमा जारी रखना चाहते हैं। जब उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में प्रथम उत्तरदाता सुगुना की मृत्यु हो गई, तो उच्च न्यायालय के लिए उचित कदम यह था कि वह सबसे पहले यह तय करे कि उसके कानूनी प्रतिनिधि कौन थे। इस उद्देश्य के लिए, उच्च न्यायालय, जैसा कि उसने वास्तव में किया भी, आदेश 22 दी.प्र.स. के नियम 5 के प्रावधान के तहत, निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए, इस प्रश्न को अधीनस्थ न्यायालय को भेज सकता था। निष्कर्ष प्राप्त करने के बाद, उसे उस प्रश्न पर निर्णय लेना चाहिए था, और कानूनी प्रतिनिधि माने जाने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को अभिलेख पर आने की अनुमति देनी चाहिए थी। तभी अपील में मृतक

उत्तरदाता की संपत्ति का प्रतिनिधित्व हो सकता था। लेकिन इस मामले में, जिन तारीखों पर अपील की सुनवाई और निपटारा हुआ, उसमें प्रथम उत्तरदाता की मृत्यु हो चुकी थी, और यद्यपि उसकी संपत्ति के प्रतिद्वंद्वी दावेदारों ने उसकी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने का दावा पेश किया था, फिर भी यह विवाद कि कानूनी प्रतिनिधि कौन होना चाहिए, अनिर्धारित रह गया, और परिणामस्वरूप मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। तीसरे उत्तरदाता को मृतक प्रथम उत्तरदाता के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में तभी जोड़ा गया जब अपील को स्वीकार करते हुए अंतिम निर्णय सुनाया गया। यह एक मृत व्यक्ति के विरुद्ध अपील की सुनवाई के समान है। यह स्पष्ट रूप से कानूनन अस्वीकार्य है। इसलिए, हमारा मानना है कि पूरा निर्णय अमान्य और निष्प्रभावी है।

13. हम इसे एक और नज़रिए से देख सकते हैं। सुगुना द्वारा मुकदमे में मांगी गई राहत ऐसी थी जिसके संबंध में मुकदमा करने का अधिकार उसके कानूनी प्रतिनिधियों के पास बना रहता अगर मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती। उसने मुकदमे का सफलतापूर्वक मुकदमा चलाया और विलेख को अमान्य घोषित करने वाली डिक्री प्राप्त की। उक्त डिक्री तब तक लागू रहेगी जब तक कि इसे कानून द्वारा ज्ञात तरीके से रद्द नहीं कर दिया जाता। इसे पीड़ित पक्ष द्वारा दायर अपील में रद्द किया जा सकता है, लेकिन केवल उस वादी को सुनने के बाद जिसने डिक्री हासिल की थी। किसी मामले में फैसला तभी सुनाया जा सकता है जब मामले की सुनवाई हो चुकी हो। (दी.प्र.स.) की धारा 33, आदेश 20 नियम 1 और आदेश 41 नियम 30 के माध्यम से) जब उत्तरदाता-वादी की मृत्यु हो जाती है और उसकी संपत्ति का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि अपील पर 'सुनवाई' हुई थी। जब उत्तरदाताा-वादी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख में लाना होगा और उन्हें मृतक वादी की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के रूप में सुना जाना चाहिए। यदि उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो कानून की दृष्टि में अपील की कोई 'सुनवाई' नहीं होती है। परिणामस्वरूप, निचली अदालत के फैसले को अपीलीय अदालत द्वारा बाधित या रद्द नहीं किया जा सकता है। चाहे जो भी हो।

14. तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और 19.9.2006 के निर्णय को अपास्त करते हैं, अपील को उच्च न्यायालय की फाइल में पुनः स्थापित करते हैं, निम्नलिखित निर्देशों के साथ:

(i) उच्च न्यायालय पहले मृतका के पति और दूसरी ओर उसकी भतीजियों और भतीजों के बीच विवाद का फैसला करेगा, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य और 28.11.2005 के निष्कर्षों पर विचार करने के बाद और

> *प्रतिद्वंद्वी दावेदारों की सुनवाई करेगा।*
>
> *(ii) ऐसे निर्धारण के बाद, मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों को मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अभिलेख में लाया जाएगा।*
>
> *(iii) इसके बाद, अपील की योग्यता के आधार पर सुनवाई की जाएगी और कानून के अनुसार उसका निपटारा किया जाएगा।*

17. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने **अनिल कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड (उपरोक्त)** मामले में अनुच्छेद संख्या 17 से 24 तक निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

> *"17. उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जब यह विवाद उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति मृतक वादी या मृतक उत्तरदाता का कानूनी प्रतिनिधि है या नहीं, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में उक्त व्यक्ति को अभिलेख में दर्ज करने से पहले उक्त प्रश्न का निर्धारण करे।*
>
> *18. इस मामले में, याचिकाकर्ता ने चुनौती दी है कि राम चंद्र प्रसाद शाही, जिन्होंने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अयोध्या प्रसाद सिंह ट्रस्ट के सचिव होने का दावा किया था, विधिवत रूप से उपर्युक्त ट्रस्ट के सचिव नियुक्त नहीं हैं और वे उपर्युक्त ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम नहीं हैं और न ही वे उपर्युक्त ट्रस्ट के कानूनी प्रतिनिधि हैं। यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 19.05.2009 के विवादित आदेश को पारित करने से पहले दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 5 के तहत कोई जांच नहीं की, बल्कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया।*
>
> *19. उत्तरदातााओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 5 के तहत निर्धारित जाँच के बराबर है, लेकिन मेरे विचार में, केवल अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन उचित जाँच के बराबर नहीं है क्योंकि जाँच में उक्त जाँच के दोनों पक्षों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है, लेकिन वर्तमान मामले में, सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 19.05.2009 को आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले, उपर्युक्त राम चंद्र प्रसाद शाही की स्थिति के बिंदु पर पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं*

दिया।

20. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सक्षम प्राधिकारी ने समिति के प्रस्तावों की फोटोस्टेट प्रति पर भरोसा किया और उपरोक्त समिति के प्रस्तावों के मूल दस्तावेजों को मंगाने में कोई कष्ट नहीं उठाया, विशेषकर उस स्थिति में जब याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जोरदार ढंग से दलील दी कि समिति के प्रस्तावों की फोटोस्टेट प्रतियां जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज हैं और इसलिए, मेरे विचार से, सक्षम प्राधिकारी का आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि में टिक नहीं सकता।

21. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि सक्षम प्राधिकारी ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 5 के प्रावधान की पूरी तरह से अनदेखी की है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विशेष रूप से यह दलील दी कि राम चंद्र प्रसाद शाही को उक्त ट्रस्ट का सचिव नियुक्त नहीं किया गया था और संबंधित ट्रस्ट वर्ष 1976 में ही अपना अस्तित्व खो चुका था जब संबंधित ट्रस्ट की संपूर्ण संपत्तियां राज्य में निहित हो गई थीं।

22. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि कानून में प्रावधान के अनुसार प्रतिस्थापन का उद्देश्य केवल मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करना है किसी मुकदमे में और किसी व्यक्ति का प्रतिस्थापन मात्र विवादित संपत्तियों के संबंध में उसके अधिकार और स्वामित्व की घोषणा नहीं है। प्रतिस्थापित व्यक्ति केवल कानूनी अदालत के समक्ष मुकदमे में मृतक के हित की पैरवी और रक्षा कर सकता है, लेकिन किसी मुकदमे में मृतक के स्थान पर किसी व्यक्ति को प्रतिस्थापित करने से पहले, न्यायालय यह देखने के लिए बाध्य है कि मृतक के स्थान पर उचित व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है या नहीं और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसका मृतक के विरुद्ध प्रतिकूल हित हो, मृतक के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और इसीलिए दी.प्र.स. का आदेश 22 नियम 5 न्यायालय पर यह निर्धारित करने का कर्तव्य डालता है कि यदि उपरोक्त तथ्य के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो कोई व्यक्ति मृतक का कानूनी प्रतिनिधि है या नहीं।

23. आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 5 के तहत दिए गए प्रावधान का पालन नहीं

> *किया है और इसलिए, मेरे विचार से, आक्षेपित आदेश कायम नहीं रह सकता क्योंकि यह कानून का पूर्ण उल्लंघन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है।*
>
> *24. तदनुसार, उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, इस रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और दिनांक 19.05.2009 का आक्षेपित आदेश, एतद्द्वारा, निरस्त किया जाता है और मामला सक्षम प्राधिकारी को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वह दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 5 के तहत प्रावधानित उचित जांच के बाद कानून के अनुसार नया आदेश पारित करे।"*

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दशरथ राव काटे बनाम बृज मोहन श्रीवास्तव (उपरोक्त)** मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

> *"इसमें यह प्रश्न शामिल था कि क्या आदेश 22, नियम 5 के तहत संक्षिप्त कार्यवाही में प्राप्त निष्कर्ष अभी भी मुकदमे में पूर्वन्याय के रूप में कार्य करते हैं या नहीं और यह प्रश्न कि क्या कानूनी प्रतिनिधि का निर्णय आदेश 22, नियम 5 के तहत किया जा सकता है, इस मामले में शामिल प्रश्न नहीं था।"*

19. इस न्यायालय ने **शिव धर्मा नंद @ देव शंकर तिवारी एवं अन्य बनाम श्याम लाल चौहान एवं अन्य (उपरोक्त)** के मामले में अनुच्छेद 13 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

> *"13. किसी मुकदमे या अपील में या किसी ऐसी कार्यवाही में किसी मृत पक्षकार के स्थान पर किसी व्यक्ति का प्रतिस्थापन अपने आप में उस व्यक्ति के पक्ष में उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं बनाता है; इसलिए, पक्षकारों के बीच मुकदमे में शामिल मुद्दों के प्रभावी न्यायनिर्णयन के लिए सभी आवश्यक या उचित पक्षों को अभिलेख पर लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस संबंध में जग नारायण सिंह बनाम मथुरा प्रसाद सिंह, 1999 (3)पीएलजे आर 650 में दर्ज मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एस. चरणजीत सिंह बनाम भारतिंदर सिंह, AIR 1988 पंजाब और हरियाणा एआईआर में दर्ज मामले में भी यह माना था कि ऐसे गहन रूप से विवादित मामलों में, उचित तरीका यह होगा कि दोनों दावेदारों को संहिता के आदेश XXII नियम 5 के तहत पक्षकार बनाया जाए।"*

20. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, मुझे लगता है कि कानून सुव्यवस्थित है और किसी मृतक पक्ष के कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि के प्रतिस्थापन से संबंधित विवाद की

स्थिति में, न्यायालयों को दी.प्र.स. के आदेश 22 नियम 5 के तहत जांच करनी चाहिए। उपरोक्त निर्णय भी दी.प्र.स. के आदेश 22 नियम 5 के तहत जांच करने के अपने विचार में सुसंगत हैं, जब मृतक पक्ष के प्रतिस्थापन के संबंध में विवाद हो, मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा। मेरा मानना है कि जब याचिकाकर्ता ने *सपना कुमारी* को मृतक *ज्वाला प्रसाद गुप्ता* की कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि के रूप में प्रतिस्थापित करने पर आपत्ति जताई थी, तो निचली अदालत को दी.प्र.स. के आदेश 22, नियम 5 के तहत जांच शुरू करनी चाहिए थी और जांच के बाद, निचली अदालत को जांच के परिणाम के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए थी और *सपना कुमारी* को मृतक *ज्वाला प्रसाद गुप्ता* की कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि के रूप में बिना किसी जांच के प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता था।

21. उपरोक्त के मद्देनजर, इस आवेदन को स्वीकार किया जाता है और विद्वान उप-न्यायाधीश-द्वितीय, पूर्णिया द्वारा स्वत्व वाद संख्या 77/2005 में पारित दिनांक 05.02.2018 के आदेश को अपास्त किया जाता है और दिनांक 20.07.2015 की याचिका को बहाल किया जाता है।

22. दिनांक 20.07.2015 की याचिका को निचली अदालत में इस निर्देश के साथ बहाल किया जाता है कि निचली अदालत पहले *सपना कुमारी* और याचिकाकर्ताओं के बीच विवाद का निपटारा करेगा और यह तय करेगा कि *सपना कुमारी* मृतक *ज्वाला प्रसाद गुप्ता* की कानूनी उत्तराधिकारी/कानूनी प्रतिनिधि हैं या नहीं। इसका निर्णय दी.प्र.स. के आदेश 22, नियम 5 के प्रावधान के अनुसार एक जाँच करके किया जाएगा। जाँच के बाद, निचली अदालत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर दिनांक 20.07.2015 की याचिका पर आदेश पारित करेगा।

23. निचली अदालत को *सपना कुमारी* द्वारा प्रतिस्थापन के लिए दायर दिनांक 20.07.2015 की याचिका पर इस आदेश के संप्रेषण के तीन महीने के भीतर निर्णय करना

होगा, उसके बाद मुकदमे का निर्णय एक वर्ष के भीतर किया जाएगा, अर्थात पूरी कार्यवाही इस आदेश के संप्रेषण के 15 महीने के भीतर समाप्त होनी चाहिए।

24. निचली अदालत असहयोगी पक्ष के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करेगा और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन नहीं देगा। निचली अदालत उच्च न्यायालय में किसी भी दीवानी विविध या किसी आवेदन के लंबित रहने मात्र से अपने कार्य नहीं रोकेगा।

(संदीप कुमार, न्यायमूर्ति)

शिशिर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।